(b) and (c) The estimates of economic growth rate, as compiled by respective state Directorates of Economics and Statistics, for the year 1995-96 are given in the Statement (*See* below)

As per the available estimates, State of Maharashtra is having the highest economic growth rate of 8.5% in 1995-96.

(d) The average growth rate of the country in the last three years was 7%.

Statement

Annual Growth Rate of NSDP at Constant (1980-81) Prices from 1993-94 to 1995-96

As On 7.11.1997
(Per cent)

Sl. No.	State/U.T.	1993-94 (A)	1994-95 (P)	1995-96 (Q)
1.	Andhra Pr.	9.7	0.0	5.7
2.	Arunachal Pr.	14.4	4.2	7.4
3.	Assam	3.9	3.4	1.5
4.	Bihar	3.2	8.4	6.9
5.	Goa	4.2	3.1	0.7
6.	Gujarat	−1.5	13.2	−2.0
7.	Haryana	4.5	7.2	1.9
8.	Himachal Pr.	3.9	5.4	7.1
9.	J & K	3.9	—	—
10.	Karnataka	7.6	4.0	5.4
11.	Kerala	10.0	7.6	6.2
12.	Madhya Pr.	9.2	3.0	4.0
13.	Maharashtra	10.8	6.2	8.5
14.	Manipur	4.2	—	—
15.	Meghalaya	7.0	2.8	5.5
16.	Nagaland	1.8	—	—
17.	Orissa	6.4	3.6	5.7
18.	Punjab	4.3	4.4	3.3
19.	Rajasthan	−8.3	19.1	0.2
20.	Sikkim	—	—	—
21.	Tamil Nadu	9.4	9.5	0.1
22.	Tripura	11.0	7.4	—
23.	Uttar Pradesh	1.9	3.3	3.2
24.	West Bengal	8.0	5.4	7.4
25.	A & N Islands	7.9	6.3	—
26.	Delhi	8.9	8.5	—
27.	Pondicherry	−3.3	—	—

बड़े निगमित क्षेत्रों को दिया गया ऋण

716. **श्री सूर्यभान पाटिल वहाडणे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से लघु उद्योगों सहित बड़े निगमित क्षेत्रों को वर्ष 1992 से आज तक प्रतिवर्ष कितना ऋण उपलब्ध कराया है;

(ख) इन सभी के पास जब तक ऋण की बकाया राशि कितनी है और इस ऋण को वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या इन सबने सीमा शुल्क, उत्पाद कर, चुंगी और अन्य करों का भुगतान कर दिया है, यदि हां, तो उसका क्षेत्रवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि मार्च 1992, 1993, 1994, 1995 और 1996 के अंत की स्थिति (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े और मझौले उद्योगों और लघु उद्योगों को दिए गए बकाया अग्रिम निम्नानुसार थे:—

(रु० / करोड़)

वर्ष	बड़े एवं मझौले		लघु उद्योग	
	अग्रिम	अतिदेय**	अग्रिम	अतिदेय
मार्च, 1992	38480.81	5457.70	17566.86	3946.32
		(14.18)		(22.46)
मार्च, 1993	49379.19	7040.06	19242.88	4647.38
		(14.26)		(24.15)
मार्च, 1994	49649.79	7542.87	20924.42	5033.39
		(15.19)		(24.06)
मार्च, 1995	57626.40	7178.94	25056.92	5162.46
		(12.46)		(20.60)
मार्च 1996	73418.42	9183.26	29396.86	5947.56
		(12.51)		(20.23)

** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े अग्रिमों के अतिदेय के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

सरकार ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं की देयराशियों की वसूली को तेज करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण गठित किए हैं। सरकार और आरबीआई भी बैंकों के, ऋण मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ करने और अग्रिमों की निकट निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय में महाप्रबंधक के प्रभार के अंतर्गत वसूली कक्ष गठित किए गए हैं। बैंकों के निदेशक मंडल कभी नियमित आधार पर वसूली की स्थिति की समीक्षा करते हैं।

(ग) लघु मझौले और बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा भुगतान किए जाने वाले सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, चुंगी तथा अन्य कर के बारे में क्षेत्र-वार और वर्ष-वार एकत्र की जाने वाली सूचना में लगने वाले समय और श्रम प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

Credit Requirements of SSI Sector

717. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have directed the public sector banks to give preference to Village Industries, tiny industries and other small scale units while meeting the credit requirements of the SSI sector;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the banks are following these directions in the right earnest in Gujarat;

(d) if so, whether Government have assessed the performance of each public sector bank in the State in this regard;

(e) if so, the details thereof, bank-wise; and

(f) steps Government propose to take in respect of those banks which are not following directives in SSI sector of Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) and (b) Yes, Sir. Based on the recommendations of the P.R. Nayak Committtee, the Reserve